₹200 cr earmarked for Sardar Patel statue

PNS ■ NEW DELHI

The Government allocated ₹200 crore from Central funds to fulfil the pet project started by Narendra Modi as Gujarat Chief Minister in raising the largest statue of Sardar Vallabh Bhai Patel as a symbol of unity in the State.

"The Gujarat Government has embarked upon the mission to build the largest statue of Sardar Vallabh Bhai Patel. Sardar Patel stands as the symbol of the unity of the country. To support the Gujarat Government in this initiative to erect the statue of unity, I propose to set aside a sum of ₹200 crore," Finance Minister Arun Jaitley said in his Budget speech.

It was Modi who had laid the foundation stone of the statue in October 2013 on the 138th birth anniversary of the first Home Minister of the country, also called the 'Iron Man of India'. The total height of the statue from its base is planned to be 240 metre consisting base level of 58 metre and statue of 182 metre.

The monument is being built on a public-private partnership model, with most of the money raised through public contribution and Gujarat Government has already allocated ₹100 crore for the project.

The Pioneer, New Delhi Date: 11 July 2015

Sardar Patel's land 'sold' for lowly amount

Manas Dasgupta

- **Unusually low sale price of Rs. 2.5 lakh attracted authorities' attention**
- **Prima facie, a fraudulent deal; but revenue records need to be checked: collector**

AHMEDABAD: A piece of land reportedly gifted to the country's first Union Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel, has been "sold" at a throwaway price, with the "thumb impression" claimed to be that of the Iron Man of India.

The 1.39 hectares in Gadava village in Kaira district, Sardar Patel's home district in central Gujarat, was so far showed on the official record as owned by him. The land was used for grazing cattle.

The land was suddenly found to have been "sold" by one Vallabhbhai Zaverbhai Patel, a 90-year-old resident of nearby Vadavadi village, to one Bhupendra Dabhi.

What attracted the attention of the authorities was the low price shown in the official sale deed. The land was claimed to have been sold for Rs. 2.5 lakh, when its present market price is in the region of Rs. 60 lakh.

The deal attracted the notice of the local village sarpanch, Chiman Chauhan, who in turn alerted the Union Minister of State, Dinsha Patel, who hails from that district.

Mr. Dinsha Patel, in turn, brought it to the notice of the district authorities, and the land deal was suspended till further orders.

Mafia hand suspected

According to Mr. Chauhan, it must be the handiwork of the land mafia. The low price was presumably to escape government taxes.

Following Mr. Patel's complaint, Collector M. V. Pargi stayed all transactions on the land till further orders, and has summoned both the buyer and the seller on July 17 for questioning.

Mr. Pargi said it *prima facie* appeared to be a fraudulent deal, but he would take a decision only after checking all the revenue records, including if the land was owned by the Iron Man of India, who gifted the land to him, and relevant documents to establish the owner of the land.

I was unaware: buyer

The buyer claimed he had no knowledge that the land was owned by Sardar Patel.

The Hindu Dated 15 July 2015

जलियांवाला बाग के मिट्टी-पानी से जुड़ेंगे

DAINIK JAGRAN 13 DEC 2013 921

सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनेगी नई मिसाल

■ शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

अखंड भारत के शिल्पी लौहपुरुष सरदार पटेल की याद में नर्मदा नदी पर बनने वाली 182 मीटर ऊंची प्रतिमा 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' की नींव में जलियांवाला बाग और स्वर्ण मंदिर का मिट्टी-पानी भी लगेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रशासनिक अमला देश के हर राज्य में घूमकर समर्थन जुटा रहा है। वहीं, रविवार को देश में 700 से ज्यादा जगहों पर रन फॉर यूनिटी के जरिए भारत एक विश्व रिकॉर्ड बनाएगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मोदी ने पटेल जयंती पर 31 अक्टूबर को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया। प्रतिमा के लिए देश के पांच लाख से ज्यादा गांवों से लोहा मांगा गया था। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी पुरुषोत्तम रूपाला ने खुद बिहार का दौरा किया। रुपाला ने बताया कि सरदार पटेल ने देश के 565 रजवाड़ों को एक किया था। इसलिए देश में 565 स्थलों पर सुबह 8 से 11 बजे तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। अब तक 700 जगहों पर दौड़ का पंजीकरण हो चुका है।

शिक्षा व कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर व जलियांवाला बाग से मिट्टी व पानी लिया है। बुधवार रात कृषि मंत्री बाबूभाई बोखिरिया के नेतृत्व में केरल पहुंचे भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने सीएम ओमन चांडी को मोदी का पत्र सौंपते हुए बताया कि प्रतिमा निर्माण में किसी तरह की राजनीति नहीं है। सरदार पटेल एकता ट्रस्ट व सिटिजन संस्था के जरिए देश के 550 गांवों में एक किट भेजी जाएगी। इसमें हर गांव से पानी, मिट्टी के साथ गांव के सरपंच व मुखिया का फोटो और कृषि के काम आए लोहे के औजार का टुकड़ा एकत्र कर गुजरात भेजा जाना है। गांव के मुखिया या सरपंच के फोटो यहां बनने वाली प्रदर्शनी में लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस विशाल प्रतिमा से देश को एकजुट करने की नरेंद्र मोदी की इस मुहिम का अहम चरण शुरू होने को है।

- रन फॉर यूनिटी से बनेगा विश्व रिकॉर्ड : रुपाला
- रविवार को देश में 700 से ज्यादा जगहों पर रन फॉर यूनिटी के लिए लोग दौड़ेंगे

देवभूमि से भी एकत्र होगा लोहा

देहरादून : अखंड भारत की एकता के सूत्रधार सरदार बल्लभ भाई पटेल की गुजरात में बनने वाली विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति में उत्तराखंड के गांवों के लोहे का ही नहीं, बल्कि मिट्टी का भी प्रयोग होगा। इसके लिए विशेष अभियान 15 दिसंबर से शुरू होगा।

गुजरात सरकार की ओर से गठित सरदार बल्लभ भाई राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को यहां टाउन हॉल में एक कार्यक्रम में जन भागीदारी के लिए शुरू किए जा रहे। राष्ट्रीय एकता के मद्देनजर जनभागीदारी के तहत शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत देश के दो लाख स्कूल-कॉलेजों में सरदार पटेल पर निबंध प्रतियोगिता होगी, जिसमें से डेढ़ लाख स्कूल गांवों के होंगे। गुजरात के जल संसाधन राज्यमंत्री नानुभाई पटेल ने कहा कि सरदार पटेल साझी विरासत हैं। देश के करीब 562 रियासतों को एक कर सरदार पटेल ने अखंड भारत का सपना साकार किया, लेकिन कुछ समय से सरदार पटेल को भुलाने की कोशिश की जा रही है।

Dainik Jagran 13 December 2013

पटेल को याद कर राजनाथ ने शुरू किया काम

काम पर सरकार

नई दिल्ली | **विशेष संवाददाता**

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ ही मंत्रालय में कामकाज शुरू कर दिया है। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर प्रगति रिपोर्ट ली और चुनौतियों के बारे में पूछा।

राजनाथ सिंह के साथ गृह राज्य मंत्री बनाए गए किरण रिजिजु ने भी गुरुवार को कार्यभार संभाला। गृह सचिव अनिल गोस्वामी और मंत्रालय के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने गुलदस्तों से राजनाथ सिंह का स्वागत किया। राजनाथ ने अपने कक्ष में पहुंचकर कार्यभार संभाला और उसके बाद संसद भवन के निकट जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए।

देर शाम दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने राजनाथ से मुलाकात की। हालांकि गृह मंत्रालय ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया है लेकिन समझा जाता है कि दिल्ली में सरकार गठन की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों ने भी राजनाथ से मुलाकात की। राजनाथ ने कहा कि वह सरदार पटेल का आर्शीवाद लेकर मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। पटेल ने देश के लिए जो कुछ किया उसे चुकाया नहीं जा सकता। देश की एकता के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है। लखनऊ सीट से जीतकर आए राजनाथ सिंह भाजपा के शीर्ष नेताओं में शुमार हैं। वह दो बार भाजपा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा पिछली एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब बतौर गृह मंत्री वह नंबर-2 की स्थिति में हैं। राजनाथ सिंह वाजपेयी सरकार में कृषि एवं भूतल परिवहन मंत्री रह चुके हैं। वाजपेयी के सपनों की परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को सिंह ने ही शुरू कराया था।

राजनाथ के समक्ष आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। नक्सली हिंसा में कमी लाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा आतंकी गतिविधियां रोकना, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ रोकना, खुफिया तंत्र को मजबूत करना, आपदा प्रबंधन के इंतजामों को बेहतर करने की चुनौती होगी। लेकिन सबसे पहले राजनाथ को आंध्र प्रदेश के विभाजन के जमीनी स्तर के कार्य को अंजाम देना है, उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक और अन्य विधेयकों की समीक्षा करेंगे। संभावना यह है कि सांप्रदायिक हिंसा निरोधी बिल को गृह मंत्रालय अब आगे नहीं बढ़ाए।

नई दिल्ली में गुरुवार को देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाते केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह। • विपिन कुमार

गृहमंत्री की चुनौतियां

• बढ़ती नक्सल हिंसा पर काबू पाना • आतंकी गतिविधियां और घुसपैठ से निपटना • बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ से निपटना • खुफिया तंत्र को मजबूत करना • आपदा प्रबंधन के बेहतर इंतजाम करना

उड्डयन क्षेत्र को बेहतर बनाएंगे राजू

तेदेपा के वरिष्ठ नेता पी अशोक गजपति राजू ने गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद नए नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने घाटे का सौदा साबित हो रहे उड्डयन क्षेत्र को बेहतर बनाने का वादा किया। चंद्रबाबू नायडू की पूर्ववर्ती सरकार में वित्त एवं राजस्व मंत्री की भूमिका निभाने वाले राजू विजिनगरम के शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

क्या किए वादे : • उड्डयन क्षेत्र में भारी घाटे के कारणों की समीक्षा करेंगे • मंत्रालय को जनोन्मुखी और सबके लिए सुलभ बनाएंगे • क्षेत्र के सभी प्रतिस्पर्धियों को समान अवसर मुहैया कराएंगे

विदेशी कैसिनो नहीं

पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले श्रीपद नाइक ने गुरुवार को कहा कि वह विदेशी कैसिनो को खोले जाने की इजाजत देने के खिलाफ हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नाइक ने कहा कि गोवा सरकार पहले ही नई गेमिंग पॉलिसी ला रही है और अंतत : वही विदेशी कैसिनो पर फैसला लेगी।

क्या किए वादे : • पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी देना होगा प्राथमिकता • लालफीताशाही कम कर बुनियादी ढांचे का विकास

योजनाओं में तेजी लाएंगे

फरीदाबाद से सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण पाल गुर्जर ने गुरुवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि यूपीए के दस साल के शासन में हाइवे सेक्टर की दुर्गति हुई है और इसे पटरी पर लाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

क्या किए वादे : • दिल्ली को जाम से मुक्ति, हादसों को रोका जाएगा • लटके राजमार्ग प्रोजेक्ट को पटरी पर लाएंगे • सड़कों की गुणवत्ता सुधारी जाएगी

Hindustan Delhi Dated: 30 May 2014

विरासत पर यह कैसी सियासत

■ राजकिशोर

जो लोग जवाहरलाल नेहरू और पटेल के मतभेदों की चर्चा कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर दोनों की साझा रजामंदी से संविधान में धारा 372 क्यों डाली गई, जिसे एक ओर तो अस्थायी प्रावधान बताया गया और दूसरी ओर इसके तहत ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे कश्मीर का विशेष दर्जा लगातार चलता रहे और किसी भी तरह उसे हटाया न जा सके

जवाहरलाल नेहरू और वल्लभभाई पटेल में कुछ मामलों में मतभेद था, लेकिन सवाल है कि

इससे नेहरू कैसे छोटे हो गए और पटेल कैसे बड़े हो गए? नरेंद्र मोदी के समर्थक जिस तरह दोनों दिवंगत नेताओं में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, वह राजनीति नहीं है तो क्या है? नेहरू और पटेल, दोनों ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे और पार्टी के भीतर दोनों के अपने समर्थक थे। सरदार पटेल जवाहरलाल के कैबिनेट में गृह मंत्री ही नहीं, उप प्रधानमंत्री भी थे। अगर जवाहरलाल नेहरू वल्लभभाई पटेल की इज्जत न करते होते, तो क्या यह स्थिति संभव थी। सवाल यह भी है कि अगर पटेल नेहरू का सम्मान नहीं करते होते, तब वह नेहरू के नेतृत्व में काम करने के लिए कैसे सहमत होते?

सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी अपने इन दोनों शिष्यों को बहुत मानते थे। पटेल उनकी विचारधारा के ज्यादा करीब थे और जवाहरलाल को वह अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद अपने राजनीतिक गुरु के प्रति पटेल की आस्था बनी रही, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपना अलग रास्ता अपनाया। जिस ग्राम स्वराज की बात करते महात्मा गांधी थकते नहीं थे, वह नेहरू को कभी अपना नहीं लगा। पटेल उससे पूरी तरह सहमत थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? नेहरू और पटेल दोनों एक ही तरह की राज्य व्यवस्था चला रहे थे। दोनों के रहते भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया गया, जिसमें ग्राम स्वराज का कहीं नाम नहीं था। बहुत से गांधीवादियों के जोर देने पर पंचायत शब्द रख तो लिया गया, परंतु प्रशासन की एक इकाई के रूप में नहीं, संविधान के नीति निदेशक तत्वों में।

नेहरू और पटेल के बीच मतभेद के जो तीन मामले अक्सर उद्धृत किए जाते हैं, उनका विश्लेषण उपयोगी होगा। सरदार पटले सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य में राज्य की सहायता चाहते थे जबकि नेहरू ने साफ तौर पर इसके लिए मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू का तर्क था कि किसी भी धर्म का उन्नयन करना या उसके धर्मस्थानों का निर्माण या पुनर्निर्माण करना राज्य का काम नहीं है। अच्छी बात यह है कि पटेल ने इसे टकराव का बिंदु नहीं बनाया। शायद वह समझ गए कि धर्मनिरपेक्षता की मांग यही है। इसलिए उन्होंने इस अध्याय को वहीं बंद कर देना उचित समझा। सच्चाई यह है कि उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत रूप से भी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में रुचि नहीं ली। सोमनाथ मंदिर फिर से बना, पर सरदार पटेल के देहांत के बाद। आश्चर्य यह है कि नेहरू और पटेल के बीच जिस मसले को लेकर कोई संघर्ष नहीं हुआ, उसे ही आज संघर्ष का बिंदु आखिर क्यों बनाया जा रहा है।

जहां तक हैदराबाद और कश्मीर के भारत में विलय का सवाल है तो वर्तमान में इसे भी संघर्ष बिंदु के रूप में पेश किया जा रहा है। यह सही है कि इन दोनों ही मामलों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किसी भी हाल में बल प्रयोग करना नहीं चाहते थे। एक दृष्टि से यह ठीक भी था। नए भारत की नींव हिंसा पर नहीं रखी जा सकती थी। जवाहरलाल नेहरू के दिल में दो बातें थीं, जनमत गणना या संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता। बहुत से लोगों का खयाल है कि यदि कश्मीर और हैदराबाद को भारत में लाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रास्ता अपनाया गया होता, तो यह ज्यादा बेहतर हो सकता था। ऐसी स्थिति में तब शायद कश्मीर समस्या नाम की चीज पैदा ही नहीं होती।

इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कश्मीर में सैनिक कार्रवाई जम्मू और कश्मीर सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए की गई थी। इसलिए हैदराबाद के निजाम के साथ जो हुआ, वही कश्मीर के राजा हरि सिंह के साथ किया गया, यह नहीं कहा जा सकता। स्वयं राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि सेना भेजकर पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से उनके राज्य को बचाया जाए। उस मौके पर भारत के सामने दो विकल्प थे। इसमें एक विकल्प यह था कि भारत सरकार तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करती और राजा हरि सिंह की बात मानकर सेना भेज दी जाती और आक्रमणकारियों को भगाकर जम्मू एवं कश्मीर को वहां के राजा के हाथ में सौंप दिया जाता। दूसरा विकल्प यह था कि पहले कश्मीर का भारत में विलय होता तब सैनिक सहायता दी जाती।

विलय की शर्त में कोई बुराई नहीं थी। नेहरू सेना भेजने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि यह उन्हें लोकतांत्रिक रास्ता नहीं लग रहा था। पटेल ने

Dainik Jagran Dated: 10 November 2013